



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 1984/पौष 23, 1905

No. 6]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 1984/PAUSA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 3—आई टी सी (पी एन)/84

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1984

विषय : भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1983 के संबंध
में लाइसेंस शर्तें, स्वीडन सहायता

मि० सं० आई टी सी/23(10)/83.—भारत स्वीडन विकास
सहयोग समझौता, 1983 के अंतर्गत आयातों के संबंध में लागू
होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में
दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिभूचित की जाती हैं।

हस्ताक्षर

(प्रकाश खंड जैन)

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

अजीत मेठ, संयुक्त मुख्य नियंत्रक
आयात निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 3—आई०
टी सी (पी एन)/83 दिनांक : 13 जनवरी, 1984 का परि-
शिष्ट—भारत स्वीडन विकास समझौता, 1983 के अधीन
लाइसेंस शर्तें

अमुख

भारत-स्वीडन विकास समझौता 1983 के अंतर्गत
स्वीडन को सहायता दो खण्ड से युक्त है—(1) सामान्य
आयात और (2) स्वीडन से आयात। प्रथम खण्ड के
सामने में प्रतियोगी विश्वव्यापी निविदा के आधार पर आयात
विश्व में कहीं से भी किए जा सकते हैं, परन्तु, द्वितीय
खण्ड के सामने में आयात केवल स्वीडन से किए जा सकते
हैं अर्थात् माल का स्वीडन में विनिर्मित होना आवश्यक है।

आयात लाइसेंस

आयात लाइसेंस लागत-ब्रीमा-भाड़ा के आधार पर
संवैधानिक करने के लिए 4 महीने की और पोतलदान एवं
भुगतान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता
के साथ जारी किये जाएंगे। सभी पोतलदान लाइसेंस की वैधता

अवधि समाप्त होने से एक महीने के भीतर अवश्य पूर्ण करने चाहिये।

2. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एड जोरित "आयात-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1983 सामान्य आयात" अथवा "भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1983 स्वीडन से आयात" जैसा भी नामला ही होगा। लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में प्रत्येक "आर०/एम०डब्ल्यू०" होने। ये प्रत्येक आयात लाइसेंस अंजने समय मुख्य निर्यातक, आयातनिर्यात के पत्र में भी दृष्टरूप जाएंगे।

3. आयात लाइसेंस को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा संभाव्य निधि, जिस तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, निर्दिष्ट करने हुए आयात लाइसेंस को प्राप्ति के तत्त्व से आर्थिक कार्य विभाग (इन्चार्ज आर० ए० अनुभाग) को सूचित करना चाहिये।

4. जब तक नीचे के पैरा 21 में परामर्शित-1 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण संविदा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक संविदा करने से संबंधित शर्त का पालन किया गया नहीं माना जाएगा।

5. यदि, छप शर्त का पालन 4 महीने के भीतर नहीं किया जाएगा तो आयात लाइसेंस अवैध हो गया समझा जाएगा।

6. लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्तों का पालन न करने के कारण देने हुए एक आवेदनपत्र देने पर आयात लाइसेंस पुनर्विध किया जा सकता है। पुनर्विधकरण के लिए आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा शर्तों के आधार पर विचार किया जाए और लाइसेंस संविदा के लिए अधिक से अधिक अगले बार महीनों की अवधि के लिए पुनर्विध किया जाएगा। इस अवधि से आगे किसी प्रकार का पुनर्विधकरण करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (आ०एम० अनुभाग) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

संविदा करना

7. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा जसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया विदेशी और विदेशी संभरक द्वारा उन आदेश का स्पष्ट जवाब में स्वीकृति पत्र हो सकती है। मनुद्वारा संभरकों ने भारतीय अधिकारियों के लिए आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा आदेश का पूर्णिकरण स्वीकार्य नहीं है।

8. दो पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार-बार संशोधित/परिगोधित करने से संबंधित पत्र व्यवहार के अनुक्रम में समाविष्ट संविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। ऐसे

समयों में, दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत शर्तों सहित और हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है।

9. सामान्यतः पक्की कीमतों के आधार पर लाइसेंस के पूरा मूल्य के लिए विदेशी संभरक के साथ एक संविदा की जाती है। लेकिन, विशेष कारणों से यदि एक से अधिक संविदा करना आवश्यक हो जाता है तो इसके लिए कारण देने हुए आर्थिक कार्य विभाग की पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए।

संविदा की शर्तें

सामान्य

10. निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे लागत-बीसा-भाड़े या लागत और भाड़ा के आधार पर संविदा करें। उन्हें चाहिए कि वे जहाज निशुल्क पर्यन्त मूल्य बीसा पसार एवं भाड़े को अलग अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

संविदा सरकारी अधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा केवल लागत और भाड़ा के आधार पर ही होनी चाहिए।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त शुल्क मूल्य के आधार पर कोई संविदा करने का इच्छुक है, तो पार्टी को ऐसा करने के लिए कारण देने हुए आर्थिक कार्य विभाग (आई०एम० अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन मांगना चाहिए।

11. यदि विदेशी संभरक के भारतीय एजेंट को कोई कमीशन चुकाया जाता है, तो उसे संविदा के मूल्य से अलग दिखाया जाएगा। भारतीय एजेंट का कमीशन भारतीय रुपय में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति समंजित किया जाएगा।

12. संविदा का मूल्य उसी मुद्रा में व्यक्त होना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है। इन धनराशियों का रुपये में परिवर्तन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड-15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिनियमित विनियम की दर पर और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को परिचालित मुद्रा विनियम की दरों पर किया जाएगा।

संविदाओं की मूल्य सीमाएं

13. प्रत्येक संविदा का मूल्य 75 हजार रुपये के बराबर की धनराशि से कम नहीं होना चाहिए।

माल का उद्गम स्थान

14. (i) प्रथम खण्ड अर्थात् आमुख में उल्लिखित सामान्य आयात खण्ड के मामले में, किसी भी देश से बिना प्रतिबन्ध के आयात किए जा सकते हैं और ये आयात जहां तक माध्य हो, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर होने चाहिए।

[illegible]

1. የግብርና ሚኒስቴር የሚመለከት ሲሆን በዚህ ዓመት
በግብርና ሚኒስቴር ስር ተጽእኖ የሚያደርጉ አጭር-
ጊዜያዊ እና ረጅም ጊዜያዊ የግብርና ሚኒስቴር
አጭር-ጊዜያዊ የግብርና ሚኒስቴር አጭር-ጊዜያዊ
አጭር-ጊዜያዊ የግብርና ሚኒስቴር አጭር-ጊዜያዊ
አጭር-ጊዜያዊ የግብርና ሚኒስቴር አጭር-ጊዜያዊ (I)

(2) शिवराज का लालच प्राप्त आशयों के लिए गुण आदेश की विवेचना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है कि वह स्वयं ही अपने जीवन में इस प्रकार के व्यवहार को अपनाने से बचाव ले सके।

(3) ਮਾਮਲਾ ਖਾਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।

(3) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।

(4) ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪੰਨਾ 1

सर्वप्रथम १२ अंग का ब्राह्मण कवच लेनी की अपेक्षा जल
कि अपाकक इला व सारी दस्तोखत प्रस्तुत कर देना गुण
है।

22. यदि संवत् १९८३ ई. अक्टूबर १५ और १६ के दिनों के लिए वृष है और यदि १९८३ के अक्टूबर १७-१८ के दिनों अक्षय्य संवत् है तो फिर संवत् १९८३ ई. के लिए वृष कौन सा होगा ?

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

बीजकों पौन परिवहन दस्तावेजों का एक सेट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ठीक उसी समय भेजेगा जिस समय वह ऐसे दस्तावेज उस भारतीय बैंकर को भेजता है जिसने साख-पत्र खोला है। भारतीय बैंकर के लिए इस सम्बन्ध में उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले साख पत्र में एक शर्त शामिल करना आवश्यक है। तथ्य यह है कि इस प्रकार अपरकाम्य पौन परिवहन दस्तावेजों के भेजे गए सेट की विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंकर को भेजे गए व्याख्यात्मक पत्र में लिखा जाएगा, बाद वाला (भारतीय बैंकर) दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करने से पहले इस बात की विशेष रूप से जांच करेगा।

25. (1) भुगतानों की व्यवस्था करते समय भारतीय आयातक फार्म "ए-1" की एक अतिरिक्त प्रति भरेगा जो उसके बैंक द्वारा भुगतान होते ही आयातक को सूचना देते हुए एक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली को भेजी जाएगी। वह पत्र जिसके साथ प्रपत्र "ए-1" साथ ही साथ प्रपत्र "ए-1" भेजे जाएंगे उसमें क्रेडिट एवं सेगमेंट का संकेत होना चाहिए जिसके अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी किया गया था।

(2) भारतीय आयातक और भारतीय बैंकर, दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित सूचना, सही पूर्ण और विशिष्ट शब्दों में संबंधित कालमों के सामने दी गई है।

(3) आगे फार्म "ए-1" पर भारतीय बैंकर के प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी इसके कार्यालय की मोहर के साथ होंगे।

टिप्पणी:—इन अवस्थाओं में यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी का अपना उत्तरदायित्व सम्बन्धित नहीं है कि सभी फार्म "ए-1" उसके बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को तुरन्त भेजे गए हैं।

*रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा धन परिषदों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रपत्र।
धन वापसी :

26. यदि विदेशीसंभरक या बीमाकर्ता से भारतीय आयातकों द्वारा कोई धन वापसी प्राप्त की जाती है तो सम्बन्धित व्यौरों के साथ प्राप्त की गई धनराशियों को प्रदर्शित करते हुए एक पूर्ण रिपोर्ट अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।

भारतीय आयातकों द्वारा वास्तविक भुगतानों की रिपोर्टें भेजना—

27. जब और जैसे ही भारतीय आयातकों द्वारा समुद्र पार संभरकों को अलग-अलग संविदाओं के मद्दे वास्तविक भुगतान कर दिए जाते हैं तो उसे निरपवाद रूप से इसकी रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। भुगतानों की रिपोर्टें भेजते समय आयातक को चाहिए कि वे भेज दी गई/भेजी जा रही प्रत्येक संविदा के मद्दे आयातित उपकरण के उद्देश्यों का संक्षेप में संकेत भी करें। ये रिपोर्ट वास्तविक भुगतान हो जाने के एक सप्ताह के भीतर ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दी जानी चाहिए।

विविध

28. लाइसेंस के अधीन अम्मत किए गए माल का उपयोग उचित उद्योगशीलता और क्षमता के साथ होना चाहिए। लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का प्राप्ति की तिथि से कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए आयात (1) ऐसे माल की पहचान के लिए आवश्यक और उसके उपयोग का सभी संबंधित रिकार्ड रखेगा, (2) क्रेडिट की रकम खर्च से संबंधित और ऐसी रकमों से प्राप्त माल और सेवाओं से संबंधित ऐसी सूचना भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण उत्पन्न करेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगा जाए और (3) भारत सरकार के प्रतिनिधियों और स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे माल और सेवाओं के उपयोग का अध्ययन करायेगा यदि वे ऐसा करने का अनुरोध करें।

29. भारतीय आयातक और विदेशी संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

30. भारतीय आयातक को आयात लाइसेंस से संबंधित किसी एक मामले या सभी मामलों के संबंध में और स्वीडन के प्राधिकारियों के साथ क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करना होगा।

31. इसमें निर्धारित किसी शर्त के किसी प्रकार उल्लंघन या भंग करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अधीन समुचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध-1

(दो प्रतियों में)

कंडिका 21(4)

सेवा में

सचिव,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग

आई०ए० अनुभाग, नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली।

विषय: भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1983 इसके
अन्तर्गत आयात।

महोदय,

उपरोक्त समझौते के अन्तर्गत.....

(माल अथवा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

के आयात के संबंध में हम निम्नलिखित व्योरे भेजते हैं:-

(क) आयातक का नाम तथा पता

(ख) आयात लाइसेंस

(1) संख्या

(2) दिनांक

(4) धनराशि

(4) कब तक वैध है—

संविदा के लिए

(ख) पोतलदान के लिए ;

(ग) विदेशी संभरक का नाम तथा पता

(घ) संविदा का दिनांक

अथवा

आदेश के लिए संभरक के अन्तिम अनुमोदन पत्र
का दिनांक

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(च) संविदा का मूल्य

जहाज पर निःशुल्क मूल्य विदेशी मुद्रा में समतुल्य

भारतीय रुपए में

भाड़ा

बीमा

जोड़

(छ) संविदा में यथा निर्धारित दिनांक विदेशी मुद्रा
संभरण की अनुसूचियों के में पोतलदान
के आधार पर विभिन्न की मुद्रा
तिथियों जिनको उपकरण
सदान किए जाएंगे
अथवा सेवाएं निष्-
प्रापित की जाएंगी, प्रत्येक
लदान अथवा निष्पादित
सेवाओं का मूल्य आधारित
होगा।

(ज) वह तिथि जिसकी संविदा
के अन्तर्गत भुगतान करने
करने होंगे:—

(1) अग्रिम भुगतान के संबंध में दिनांक विदेशी मुद्रा
में राशि

(2) अन्य भुगतानों के संबंध में

(3) यदि कोई हो तो भारतीय अधिकर्ता का कमीशन

(झ) विदेशी मुद्रा में विनिमय में
प्राधिकृत उस व्यापारी बैंक
का नाम और पता
जिसके माध्यम से साखपत्र
खोलने के लिए व्यवस्थाएं
की जाएंगी।

(ञ) उस विदेशी बैंकर का नाम
और पूरा पता जिसके
पास साखपत्र स्था-
पित किया जाएगा।

2. संविदा की 4 प्रतियां अथवा प्रत्येक आदेश तथा
स्वीकृति पत्र तथा संशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित
प्रतियां तथा आयात लाइसेंस की दो फोटो स्टेट प्रतियां संलग्न
की जाती हैं।

3. विदेशी संभरक का चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय जांच पड़ताल
के आधार पर किया गया है और प्राप्त किए गए आदेश का
एक विवरण संलग्न है। माल स्वीडन मूल के हैं और विदेशी
संभरक का माल के मूल उद्गम का प्रमाण पत्र संलग्न है।

4. आप से अनुरोध किया जाता है कि भारत स्वीडन
विकास सहयोग समझौता, 1983 के अन्तर्गत वित्त दान के
लिए संविदा अनुमोदित करा लें और उपर्युक्त संकेतित
उनके बैंकर के माध्यम से संभरकों को भुगतान के लिए
प्राधिकार पत्र जारी करें।

भवदीय,

लाइसेंसधारी

अनुबन्ध-2

(कड़िका-22)

अंख्या एक

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

प्राधिकार पत्र सं० जीआईएसआई.....

सेवा में,

(भारतीय बैंक)

विषय: भारत स्वीडन समझौता, 1983 के
अन्तर्गत की गई संविदा सामान्य आयात स्वीडन आयात
सेगमेंट

प्रिय महोदय,

सर्वश्री.....की भारत-
स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1983 के अन्तर्गत जारी

किए गए लाइसेंस संख्या दिनांक ..
 मूल्य के मद्दे ...
 रूप की धनराशि लागत
 बीमा-भाड़ा लागत तथा भाड़ा के लिए का
 संभरण करने के लिए सर्वश्री के साथ
 (विदेशी संभरक)

संविदा कर ली है। संविदा की एक प्रति संलग्न की जाती है।

2. की धनराशि में से ...
 की धनराशि भारतीय मुद्रा में
 भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के रूप में चुकाई जाती है
 इसलिए विदेशी मुद्रा में संभरक की चुकाई जाने वाली धनराशि
 जो कि स्वीडन क्रेडिट में से वित्तयुक्त की जाएगी वह
 की धनराशि होगी।

3. आपको सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक,
 यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
 को सूचना देते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख से
 30 दिनों की अवधि के भीतर
 (विदेशी संभरक)

के नाम में उनके बैंकर अर्थात् सर्वश्री
 के माध्यम से एक साखपत्र खोलने के
 लिए प्राधिकृत किया जाता है।

4. साखपत्र खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए
 कि भारतीय आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस है।

5. मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के अध्याय-13-
 ख-8 के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक
 होगा कि साखपत्र के समाप्त होने की तिथि सम्बद्ध
 आयात लाइसेंस में यथा अभिव्यक्ति पोतलदान के लिए अंतिम
 तिथि के बाद 75 दिनों से अधिक की नहीं है।

6. साखपत्र में यह भी व्यवस्था होगी कि सर्वश्री
 अपरकाम्य पोतलदान
 (विदेशी बैंकर)

दस्तावेजों के एक सेट को इस संबंध में सीधे ही सहायता
 लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ०
 बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा कि
 प्रत्येक भुगतान पूरा कर लिया गया है।

7. आपसे अनुरोध है कि भुगतान के तुरन्त बाद ही
 भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1983 दिनांक
 15 सितम्बर, 1983 के अन्तर्गत आयात करने के लिए
 लाइसेंस शर्तों की कंडिका 25 के अनुसार विदेशी संभरक को
 प्रेषित धनराशि का विवरण दर्शाते हुए प्रपत्र "ए-1" की अतिरिक्त
 प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त
 मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

8. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

अवर सचिव, भारत सरकार

1. संविदा की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि रिजर्व बैंक आफ
 इंडिया, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को प्रेषित।

2. बिना अनुलग्नक के प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1.
 (भारतीय आयातक)

2.
 (विदेशी संभरक)

3.
 (विदेशी बैंक)

यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक भुगतान पर भुगतान
 परामर्श के साथ पोत परिवहन तथा अन्य दस्तावेजों (अपरकाम्य)
 का एक सेट सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा
 नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट
 स्ट्रीट, नई दिल्ली (भारत) को भेजा जाए।

3. संविदा तथा आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ
 सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को।

4. रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनिमय विभाग बम्बई।

अवर सचिव
 भारत सरकार

अनुबध 3
 (कंडिका-26)

आयातों के संबंध में उ अवतरण, क्षति आदि के लिए
 दावों के निपटान के मद्दे विदेशी संभरकों/पोतवर्षिकों/
 बीमाकर्ताओं से प्राप्त धन वापसियों के व्योरा को दर्शाने
 वाली रिपोर्ट।

1. भारतीय आयातक का नाम

2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक

3. आयात लाइसेंस का मूल्य

4. प्राधिकार पत्र की संख्या तथा दिनांक

5. प्राप्त की गई धन वापसी की राशि

6. उसकी किस्म और धन वापसी (संक्षिप्त व्योरा दें)

7. उस सम्बद्ध प्रपत्र "ए-1" के लिए संदर्भ जिसके अन्तर्गत
 विदेशी संभरकों की प्रारम्भिक भुगतान किया गया था। (वित्त
 मंत्रालय की प्रपत्र "ए-1") भेजते समय भारतीय बैंक का नाम
 तथा उनके पत्र की संख्या तथा दिनांक का संकेत करें।

8. क्या प्राप्त धन वापसियों का प्रयोग माल की बदलाई के
 लिए किया जाना है या नहीं? यदि नहीं तो इस बात का

सुनिश्चित कर लें कि विदेशी मूद्रा विनिमय के भीतरी प्रेषण द्वारा वास्तव में धनराशि प्राप्त कर ली गई है और इसे रुपए में भुत्ता लिया गया है।

9. अन्य कोई आवश्यक व्योरे।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL.

PUBLIC NOTICE NO. 3—ITC(PN)|84

New Delhi, the 13th January, 1984

Subject : Licensing conditions in respect of Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983—Swedish Assistance.

File No. IPC|23(10)|83.—The terms and conditions governing imports under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983 as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

Sd|—

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports
& Exports

AJIT SETH, Jt. Chief Controller of Imports &
exports

Appendix to this Ministry of Commerce Public
Notice, No. 3—ITC(PN)|84 dt. Jan., 1984

Licensing Conditions Under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983

PREAMBLE

Swedish Assistance under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement (1983), consists of two segments (i) General Import and (ii) Imports from Sweden. In the case of the first segment, imports can be effected from anywhere in the world on the basis of competitive global tendering but in the case of the second segment, the Imports can be effected or services obtained only from Sweden i.e. the goods must be manufactured in Sweden.

IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis, with an initial validity period of four months for contracting and twelve months for completion of shipments as well as payments. All shipments must be completed within a month of the date of expiry of the licence.

2. Each import licence will bear a superscription "Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983—General Imports" or "Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983—Imports from Sweden" as the case may be. The suffixes in the licence code classification number will be "R|SW". These will also be repeated in the letter from the Chief Controller of Imports & Exports forwarding the Import Licence.

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (IA Section) the fact of receipt of the Import Licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. The condition regarding contracting shall not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 21 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid.

6. The import licence may, however, be re-validated on an application by the party, wherein the reasons for not complying with the requirement in time should be stated. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond this period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs (IA Section).

CONTRACTING

7. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz., the Indian importer and the foreign supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance by the foreign supplier thereof in unequivocal terms. Orders on Indian Agents of the Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agent are not acceptable.

8. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently

amending|revising the various provisions will not be generally accepted. In such cases, it is necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to and signed as such by both the parties.

9. Normally, one contract, on the basis of firm prices, has to be entered into with the foreign supplier for the whole amount of the licence. However, if, for special reasons, conclusion of more than one contract becomes necessary, prior permission of the Development of Economic Affairs should be obtained, giving reasons for doing so.

TERMS OF CONTRACT

General :

10. The importers in the private sector are required to place the contracts on C.I.F. or C&F basis. They should clearly indicate the F.O.B. price, insurance charges and freight separately.

Contract must be entered only on C&F basis, by a Government agency or a public sector undertaking.

If any importer desires to enter into a contract on F.O.B. basis, the party should seek prior permission of the Department of Economic Affairs, (IA Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

11. If any commission is to be paid to the Indian agents of the foreign supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agent's commission will be paid in India in rupees but will be set off against the total value of the import licence.

12. The value of the contract should be expressed in the currency in which the payment is to be made to the foreign supplier. The conversion of these amounts into Rupees shall be made at the rates of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and prevailing on the date of issue of the import licence.

Value Limits of Contract

13. value of each contract should not be less than amount equivalent to Rupees seventy-five thousand (Rs. 75,000/-).

Origin of Goods

14. (i) In the case of the first segment, i.e. General Imports segment, referred to in the pre-

amble, imports can be made from any country without restriction and should, as far as practicable, be on the international competitive basis.

(ii) Under the Second segment, i.e. Imports from Sweden referred to in the preamble, the goods should be manufactured in Sweden or the services to be rendered should be of Swedish origin. A stipulation as to the Swedish manufacturing of goods or Swedish origin of services shall be incorporated in the contract.

(iii) The licensee should, while submitting the contract documents referred to in para 21(iii) below, furnish a statement of the bids received and the reasons for selecting the particular supplier and goods.

Shipments :

15. The contract should spell out delivery|shipping schedules in specific terms indicating the month of each such delivery|shipments, as closely as possible.

Any subsequent deviation from the shipping schedule should be promptly notified to the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, IA Section, North Block, New Delhi.

Payment Terms

16. The Swedish assistance does not provide for deferred payments. Full payment will, therefore, be made to the foreign supplier in cash against shipments as indicated in the following paragraphs.

17. Advance Payments.—An advance payment upto a maximum of 10% of the FOB price of the supplier can be provided at the time of the contract coming into force. In the case of any deviation in this regard, prior approval of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section) should be obtained.

18. Other payments.—The amount left after the above to payment will be payable pro-rata according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

19. It should specifically be ensured that the terms of payment, e.g. amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipments etc. are set out in precise terms in the contract with details showing the schedule of deliveries|payments etc.

20. Customary Guarantee

The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

DETAILS OF CONTRACT DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED

21. Within 20 days of the conclusion of the contract the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IA Section), North Block, New Delhi.

- (i) Four certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the foreign supplier.
- (ii) Two photostate copies of the import licence (Exchange Control Copy) valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by foreign supplier of the order placed by the importer.
- (iii) Statement of bids mentioned in para 14(iii) above.
- (iv) Other particular stipulated in Annexure—I, in duplicate.

The contract will be processed only after all these documents have been furnished by the importer.

LETTER OF AUTHORITY

22. If the contract is complete, the documents etc. are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1983, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue a Letter of Authority as in Annexure—II.

Methods of Payments

23. (i) Payment to the foreign suppliers in arranged through normal banking channels by establishing a Letter of Credit.

(ii) The Indian Importer will establish a Letter of Credit only after the Letter of Authority referred to in the preceding paragraph has been issued by the Ministry of Finance; the letter of credit will strictly be in accordance with provisions of the letter of authority.

(iii) The authority dealers in foreign exchange (Indian bankers) will not provide facilities for establishing a letter of credit to any Indian importer unless a letter of authority in this regard has been received by them direct from the Ministry of Finance and Indian banker will provide such facilities or allow remittances only in accordance with the instructions contained in such a letter of authority.

1308 GI/83—2

24. It will be responsibility of the foreign banker with whom the letter of credit has been established, to forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable invoices/shipping documents at the same time as the foreign banker forwards such sets of documents to the Indian Banker which opened the Letter of Credit. It is necessary for the Indian Bankers to include a provision to this effect in the letter of credit to be established by them. The fact, that one set of non-negotiable shipping document has been so forwarded will be noted down by the foreign bankers in the covering letter to the Indian Banker. The letter (Indian Banker) will check this point in particular before taking further action on the documents.

25. (i) The Indian importer will, at the time of arranging payments, fill in an additional copy of Form 'A1'* for being sent by their Indian Banker direct to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, under advice to the importer as soon as the payment is made. The letter forwarding Form 'A1'* as well as Form 'A1' shall indicate the credit and segment under which the import licence was issued.

(ii) Both the Indian importer and Indian Banker will ensure that all the requisite information is given correctly, fully and in specific terms against the relevant columns.

(iii) Form 'A1'* will further bear the signature of the authorised officer of the Indian Banker and stamped with its official seal.

Note : These arrangements do not absolve the licence of his responsibility to ensure that all forms 'A1' are despatched promptly by his bank to the Ministry of Finance.

Refunds :

26. If any refunds are received by the Indian importers from the foreign supplier or the insurer, a full report showing the amounts received, together with relevant particulars should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi in the form given in Annexure—III.

* Application form prescribed by the Reserve Bank of India for remittances.

Reporting of Actual Payments, etc. by the Indian Importers :

27. The Indian importers should invariably report to the Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi as and when actual payments against individual contracts are made by them to the overseas suppliers. While reporting the payments, the importer should also indicate briefly the purposes to which the equipment imported against each contract has been being put to. These reports should be sent to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi within one week of the actual payments having been made.

MISCELLANEOUS

28. The goods imported under the licence should be used with due diligence and efficiency. For a minimum period of four years from the date of delivery of the goods imported under the licence, the importer shall (i) maintain all the relevant records necessary to identify such goods and their use, (ii) furnish or cause to be furnished to the Government of India such information as may be requested, concerning the expenditure of the proceeds of the Credit and the goods and services acquired out of such proceeds, and (iii) enable representatives of the Government of India and the Swedish International Development Authority to study the use of such goods and services if they so request.

29. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise between the Indian importer and the foreign supplier.

30. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the grant agreement with the Swedish Authorities.

31. Any breach or violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, and orders issued thereunder.

ANNEXURE—I (In duplicate) [para 21(iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
I. A. Section, North Block,
New Delhi.

Subject : Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983—Import under

Sir,

In connection with the import of
 (short description of the goods and

services) under the above Agreement, we furnish the following particulars :—

(a) Name and Address of Importer

(b) Import Licence :

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(iv) Valid upto

(a) for contracting

(b) for shipment

(c) Number and address of the foreign supplier :

(d) Date of the contract : :

or

Date of suppliers' final
letter of acceptance of the
order :

(e) Short description of the goods to be imported : :

In foreign
currency

In equivalent
Indian Rupees

(f) Value of the contract :

F. O. B. Price :

Freight :

Insurance :

Total

Date Value of shipment in
Foreign currency

(g) The different dates on which the equipment will be shipped or services performed, the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules as stipulated in the contract.

Amount in foreign
Date Currency

(h) The date on which payments under the contract will fall due

(i) in respect of advance payment

(i) other payments

(iii) Indian Agent's Commission, if any ?

(j) Name and full address of the foreign banker with whom the Letter of Credit will be established :

(i) Name and full address of the dealers bank authorised in foreign exchange through whom arrangements for opening a Letter of Credit will be made :

2. Four certified copies of the contract (or four copies each of the order and the letter of acceptance and of the amendment (if any), and two

photostat copies of the import licence are enclosed.

3. The selection of the foreign supplier has been made on the basis of international enquiry and a statement of the orders received is enclosed. The goods are of Swedish origin and a certificate of the origin of goods from the foreign supplier is attached.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983, and issue authorisation for payments to the suppliers through their bankers, mentioned above.

Yours faithfully,

(Licencee)

ANNEXURE—II

(Para 22)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Economic Affairs)

New Delhi,

Letter of Authority No. G. I./S.I..

To

(Indian Banker)

Subject : Contract entered under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983, General Imports/Swedish Import Segment :

Dear Sirs,

Messrs Indian Importer—have entered into a contract with Messrs.—

foreign suppliers—for the supply of—

for the amount of—
CIF/C&F under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983 against Licence No.—dated—issued thereunder for the value of Rs.—
A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of—an amount of—is to be paid as Indian Agent's Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed out of the Swedish Grant/assistance will therefore amount to—

3. You are authorised to open a Letter of Credit for—in favour of Messrs.—

(Foreign Supplier)

thirty days from the date of this letter under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the Indian Importer is in possession of a valid Import License.

5. In terms of Chapter 13B—8 of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the letter of Credit is not later than seventy five (75) days after the final date for shipment stated in the relative import licence.

6. The Letter of Credit will also provide that Messrs.—

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents as each payment is made.

7. You are also requested to forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one additional copy of the Form 'A1' showing particulars of remittances made to the foreign supplier in terms of para 25 of the Licensing Condition for imports under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1983, dated 15 September, 1983 as soon as the payments are made.

8. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Under Secretary to the Government of India.

1. Copy with a copy of the contract forwarded to Reserve Bank of India, Exchange Control Department, —

2. Without enclosures forwarded to :

- (1) (Indian importer)——
- (2) (foreign supplier)——
- (3) (foreign banker)——

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 (INDIA).

4. Controller of Aid Accounts & Audit with a copy of the contract and that of the import licence.

5. Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay.

Under Secretary to the Government of India.

ANNEXURE—III

(Para 26)

REPORT SHOWING DETAILS OF REFUNDS
FROM FOREIGN SUPPLIERS|SHIPPERS|IN-
SURERS TOWARDS SETTLEMENT OF
CLAIMS FOR SHORT LANDING, DAMAGES,
ETC. IN RESPECT OF IMPORTS

1. Name of the Indian Importer.
2. No. and date of import licence.
3. Value of the Import Licence.
4. No. and date of Letter of Authority.
5. Amount of refund received.

6. Nature of refund.
(give brief details)

7. Reference to the relative Forms 'A1' under which payment was made initially to the foreign suppliers (indicate name of the Indian Banker and reference to their letter No. and date, forwarding form 'A1' to Ministry of Finance).

8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods: if not, confirm that amount has been actually received by inward remittance of foreign exchange and encashed into rupees.

9. Any other necessary particulars.

(Signature of the Authorised
Officer of the Importing Firm)